प्रकाशन का 41 वां वर्ष

शैल

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित
निष्पक्ष
एंव
निर्भीक
साप्ताहिक
समाचार

ई – पेपर
प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक
www.facebook.com/shailshamachar

वर्ष 41 अंक – 21 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-17 सोमवार 23 – 30 मई 2016 मूल्य पांच रूपए

एच पी सी ए प्रकरण में

अनुराग को राहत और सरकार को झटका वीरभद्र के सलाहकारों की टीम सवालों में

शिमला/शैल। प्रदेश उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति राजीव शर्मा की एकल पीठ ने एचपीसीए के अध्यक्ष हमीरपुर से भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर एंवम् अन्य के खिलाफ उस मामले की एफ आई आर को रद्द कर दिया है जो इन लोगों के खिलाफ अक्तूबर 2013 में विजिलैन्स कार्यालय धर्मशाला में सरकारी काम काज में बाधा डालने के संद्धर्भ में दर्ज की गयी थी। इस एफ आई आर की जांच पूरी करके इसका चालान सी जे एम कोर्ट में दायर कर दिया था। सी जे एम कोर्ट में भी यह चालान आने के बाद अगली प्रक्रिया शुरू कर दी गयी थी और इसी सब कुछ को अनुराग ठाकुर ने प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने अनुराग ठाकुर की याचिका को स्वीकार करते हुए इस संद्धर्भ में दर्ज हुई एफ आई आर और उस पर सीजेएम कोर्ट में चली कारवाई को निरस्त कर दिया है। अनुराग एवम् अन्य के खिलाफ यह मामला बनाया गया था कि इन लोगों ने धर्मशाला स्थित विजिलैन्स के थाना में आकर नारेबाजी करके वहां उपस्थित सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को सरकारी काम काज करने में बाधा पहुंचाई है। सरकारी कामकाज में बाधा विजिलैन्स के थाना/कार्यालय में पहुंचाई गयी थी लेकिन इस मामले की शिकायत अदालत में विजिलैन्स की बजाये एस एच ओ धर्मशाला द्वारा डाली गयी। एस एच ओ धर्मशाला के काम काज में तो कोई बाधा नही डाली गयी थी इसलिये उसे यह मामला दायर करने का कोई अधिकार ही नही था। उच्च न्यायालय ने साफ कहा कि सी आर पी सी की धारा (195)(1)(a) के तहत एस एच ओ धर्मशाला इसमे शिकायत कर्ता नही हो सकते थे। The complaint filed under the signatures of SHO, PS Dharamshala cannot be termed as complaint under Section 195 (i) (a) Cr.P.C. The complaint could only be filed by the officer concerned.अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि आई पी सी की धारा 186 के मुताबिक शिकायत में यह तफसील होनी चाहिए थी कि जिन अधिकारियों के काम मे बाधा डाली गयी उनमें कौन अधिकारी क्या काम कर रहा था और किसने कैसे उसे व्यक्तिगत तौर पर काम करने से रोका। उच्च न्यायालय ने 38 पन्नो के अपने विस्तृत आदेश में सर्वोच्च न्यायालय से लेकर देश के कई उच्च नयायालयों के ऐसे मामलों मे आए फैसलों का जिक्र किया है। उच्च न्यायालय ने जिस तरह से इस मामले में सी आर पी सी की धारा 195 (1)(a) और आई पी सी की धारा 186 के प्रावधानों की अनदेखी किये जाने का जिक्र किया है उससे सरकार की मंशा पर ही बुनियादी सवाल खड़े हो जाते है और यह संदेश जाता है कि जानबूझकर यह मामले बनाये जा रहें है। इस मामले के रद्द हो जाने के बाद यह सवाल उठा है कि इसमें ऐसी बुनियादी कमिया क्यों रखी गई जिनकी जानकारी हर बड़े पुलिस अधिकारी और पूरे अभियोजन विभाग को होना आवश्यक है। क्योंकि यह पुलिस में सामान्य प्रक्रिया है कि किसी भी मामले की जांच के बाद जब जांच अधिकारी उसका चालान तैयार करता है तो वह पूरे मामले को एक बार फिर अपने बड़े अधिकारियों के संज्ञान में लाता है और उसके बाद कानूनी पहलुओं को देखने के लिए अभियोजक के पास भेजता है। यह मामला उस व्यक्ति के खिलाफ खड़ा किया जा रहा था जो तीसरी बार भाजपा का सांसद बना है। पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा है और भाजपा के युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। पूर्व मुख्यमन्त्री प्रेम कुमार धूमल और वीरभद्र सिंह के बीच किस तरह के राजनीतिक रिश्ते है इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि वीरभद्र अपने खिलाफ चल रही ईडी और सीबीआई जांच के लिये हर संभव मंच पर धूमल, अनुराग और अरूण जेटली को कोसना नहीं भूलते। इन्ही रिश्तों के कारण वीरभद्र के इस कार्यकाल में एचपीसीए की जांच ही सरकार की विजिलैन्स का प्रमुख मुद्दा रहा है। धूमल के खिलाफ चलायी जा रही संपति जांच भी इन्ही रिश्तों का परिणाम है।

वीरभद्र के लिए धूमल, अनुराग जितने बड़े मुद्दे बन चुके हैं उसमें विजिलैंस उसी अनुपात में सरकार को झटके देती जा रही है। एच पी सी ए के पहले चालान का ट्रायल सर्वोच्च न्यायालय से स्टे हो चुका है। टेलिफोन टेपिंग के मामले में भी कोर्ट से झटका मिल चुका है। ए एन शर्मा के मामले में भी मार पड़ चुकी है। इस तरह अगर इन सारे मामलों को इकट्ठा करके देखा जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि वीरभद्र के सलाहकार इस समय वीरभद्र से ज्यादा धूमल के हितों की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं।

ठेकेदारों पर मेहरबान पर्यटन विभाग करों में दी करोड़ो की राहत

शिमला/शैल। पिछले कुछ अरसे से प्रदेश की राजधानी शिमला को निखारने संवारने का काम बड़े पैमाने पर बड़े जोरों से चला हुआ है। इस विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल पर चल रहे इस काम पर स्वाभाविक रूप से नजर जा रही है काम को लेकर जितने मुहं उतनी कहावत पूरी तरह चरितार्थ हो रही है। शहर में हो रहा यह सारा काम यहां नगर निगम नही करवा रही है बल्कि इसका जिम्मा प्रदेश के पर्यटन विभाग ने उठा रखा है। इस काम के धन का प्रावधान एशियन विकास बैंक से ऋण लेकर किया जा रहा है। इस ऋण का 63% केन्द्र सरकार और 37% प्रदेश सरकार के जिम्मे है। प्रदेश के बिलासपुर, चम्बा, कांगडा, कुल्लु, मण्डी, शिमला और ऊना जिलों में 256.99 करोड़ के काम पर्यटन विभाग करवा रहा है। इसमें से 153,71,21,104 करोड़ के आबंटित हो चुके हैं और इन पर काम चल रहा है। शेष कामों पर भी जल्द ही काम शुरू हो जाने की संभावना है।

Detail of Expenditure incurred on ADB Funded Project upto 01-04-2014 to 31-03-2015

	Expenditure Head	Expenditure period (01-04-14 to 31-03-2015)	Total Expenditure
1	Incremental Administration Cost:-		
a	Salary (01-04-2014 to 31-03-2015)	1,52,63,618.00	
b	Office Expenses (01-04-2014 to 31-03-2015)	1,18,82,790.00	2,71,46,408.00
2	Civil Work Expenses:-		
a	63% (ADB Share)	6,13,56,561.00	
b	37% (HP Share)	3,60,34,805.00	9,73,91,366.00
3	Consultancy Expenses:-		
a	PMC	1,66,76,071.00	
b	DSC	1,85,71,709.00	
c	CBT/CTS/MP	76,73,573.00	4,29,21,353.00
4	Survey & Training Expenses:-	3,35,670.00	3,35,670.00
	Total		16,77,94,797.00

ote:- All taxes are bourne by the H.P Government.

Detail of Payment made under Consultancy from 1-04-2014 to 31-03-2015

S.No	Particulars	Amount
1	Project Management Consultant(PMC)	1,85,71,709
2	Design & Supervision Consultant(DSC)	1,66,76,071
3	CBT/CTS/MP	76,73,573
	Total	4,29,21,353

शिमला में जो काम किये जा रहे है उनमें माल रोड की रेस्टोरेशन का काम जून 2014 में 23,72,63,367 रूपये में आंवटित हो गया था और बारह महीने में पूरा होना था। टाऊन हाल शिमला की रेस्टोरेशन का काम सितम्बर 2014 में अवार्ड हो गया था। यह काम 18 माह में पूरा होना था और इसकी लागत 8,01,53,020 कही गयी है टूटीकण्डी वैरियर पर बहुमंजिला पार्किंग 64,57,94,064 रूपये में पूरी होनी है। इन कामों की अनुबंधित समयावधि पूरी हो चुकी है लेकिन अभी तक काम पूरे नहीं हुए हैं। इस सबमें महत्वपूर्ण यह है कि इन कामों को अंजाम दे रहे ठेकेदारो को सरकार ने विशेष राहत देते हुए इनको सारे प्रभावी करों से राहते दे दी हैं। जब इन कामों के लिये टैण्डर आमन्त्रित किये गये थे तब टैण्डर शर्तो में इस तरह की राहत का कोई जिक्र नही था। यह राहत बाद में विभाग ने अपने स्तर पर फैसला लेकर दे दी है। इस तरह करों के रूप में इन ठेकेदारों को करोड़ो का लाभ अतिरिक्त मिल गया है। कराधान विभाग इस तरह की राहत देने के लिये कैसे तैयार हो गया? लोक निर्माण और हाऊसिंग बोर्ड में काम करने वाले ठेकेदारों को भी क्या इस तरह की राहत मिल पायेगी? इस संबंध में कराधान विभाग में कोई भी कुछ कहने को तैयार नही है। पर्यटन विभाग जो सिविल कार्य ठेकेदारों से करवा रहा है उसमें भी वही निमार्ण सामग्री प्रयोग होती है जो लोकनिमार्ण और हाऊसिंग बोर्ड में होती है।

पर्यटन विभाग यह सारा काम एशियन विकास बैंक से लिये गये ऋण से करवा रहा है। यह ऋण कैसे खर्चा जाये इसके लिये विभाग ने आठ कन्सलटैन्ट नियुक्त कर रखे हैं। और इन्हे 01-04-2014 से 31-03-2015 तक 4,29,21,353 की फीस अदा की जा चुकी है। एक ओर कन्सलटैन्ट नियुक्त करके उन्हे भारी भरकम फीस दी जा रही है दूसरी ओर ठेकेदारों को करों से छूट दे रखी है। लेकिन जब ठेकेदार तय समय

शेष पृष्ठ 8 पर.....

कसौली विस में 33 करोड़ की परियोजनाओं के लोकार्पण

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सोलन जिले की कसौली विधानसभा क्षेत्र में 33 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास किए। उन्होंने जाबल – जमरोट में 33.13 लाख रुपये

की लागत से निर्मित आयुर्वेद औषधालय तथा ग्राम पंचायत हरिपुर के पट्टा बरौरी में 1.56 करोड़ रुपये की लागत से बनी उठाऊ पेयजल योजना का लोकार्पण किया। इस पेयजल योजना से क्षेत्र की 60 बस्तियों की लगभग 8000 की आबादी लाभान्वित होगी। उन्होंने 69 लाख रुपये की लागत से निर्मित उठाऊ सिंचाई योजना को हरिपुर के लोगों को समर्पित किया जो 500 बीघा भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी। उन्होंने सुबाथू में 53 लाख रुपये से बने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का लोकार्पण भी किया।

मुख्यमंत्री ने ककड़हट्टी में हाल ही में स्तरोन्नत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला का उदघाटन किया। उन्होंने मसूलखाना में एक करोड़ रुपये की लागत से निर्मित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के नये खंड का भी लोकार्पण किया।उन्होंने पट्टा – बरौरी में 97 लाख रुपये की लागत से बनने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन की आधारशिला भी रखी।

वीरभद्र सिंह ने धर्मपुर – बशोलु – कुम्हारहट्टी और चक्की मोड़ – भोजनगर – जोहड़जी सड़कों के विस्तार के लिए भूमि पूजन किए। इन सड़कों के विस्तार पर क्रमशः 1.92 करोड़ रुपये तथा 6 करोड़ रुपये की राशि खर्च होगी। उन्होंने परवाणु – खडीण – भोजनगर – बनासर – जोहड़जी – कुम्हारहटटी तथा परवाणु – जंगेशु – कसौली – धर्मपुर सड़कों के सुधार एवं इन्हें चौड़ा करने के लिए भी भूमि पूजन की रस्म निभाई। इन सड़कों के विस्तार पर क्रमशः 8.50 करोड़ रुपये तथा 11.30 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी।

राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री का हिमाचली सैनिकों की शहादत पर शोक व्यक्त

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत तथा मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने मणिपुर में आतंकवादियों से लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले दो हिमाचल प्रदेश के दो जवानों की मृत्यु पर गहरा शोक प्रकट किया है।

राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश के ये दोनों सपूत असली हीरो थे, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा की और इसकी में तत्पर सैनिकों की बहादुरी के लिये इन महान वीरों को सलाम किया।

उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति तथा शोक संतप्त परिजनों को शक्ति प्रदान करने की कामना की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिलासपुर जिले के शाहतलाई के समीप मरूड़ा गांव के निवासी सुबेदार बलदेव शर्मा तथा मण्डी जिले के गोहर निवासी राईफलमैन भुपेन्द्र कुमार ने राष्ट्र की एकता, अखण्डता एवं सुरक्षा को कायम रखने के लिये अपने प्राणों की आहूति दी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के वीर जवानों ने हमेशा ही देश की रक्षा के लिये सर्वोच्च बलिदान किया है। उन्होंने कहा कि दोनों सिपाहियों का बलिदान राज्य तथा देश के लोगों द्वारा हमेशा याद किया जाएगा।

वीरभद्र सिंह ने शोकाकुल परिवारों के साथ अपनी हार्दिक सांत्वना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोग दुःख की इस घड़ी में उनके साथ हैं। उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिये ईश्वर से प्रार्थना भी की है।

सैनिक कल्याण मंत्री डा.(कर्नल) धनी राम शांडिल ने भी दोनों हिमाचली सिपाहियों की मृत्यु पर गहरा दुःख प्रकट करते हुए शोकाकुल परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं प्रकट की हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित बनाएं

शिमला/शैल। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौल सिंह ठाकुर

ने विभाग के सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा की।

ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र के सभी सूचकांक राष्ट्रीय स्तर के मुकाबले बेहतर है जिनमें और सुधार लाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने सभी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन आपसी तालमेल तथा सहयोग से और प्रभावी बनाने पर भी बल दिया।

ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध है। प्रदेश सरकार द्वारा 66 दवाएं व उपयोगी सामग्री को अधिसूचित किया है, जो सभी स्वास्थ्य संस्थानों में निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने चिकित्सकों से इन अधिसूचित दवाईयों को मरीजों के लिए लिखने के निर्देश देते हुए कहा कि इसका उल्लंघन करने वाले चिकित्सकों के विरूद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

स्वास्थ्य मंत्री ने सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि समय पर जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने हाल ही में 104 टोल फी नम्बर आरम्भ किया है, जो लोगों की शिकायतों के निवारण के साथ – साथ परामर्श सुविधा भी उपलब्ध करवा रहा है। सरकार ने इस टोल फी नम्बर 104 पर आशा कार्यकर्ताओं द्वारा मातृ एवं शिशु मृत्यु सूचना प्रणाली आरम्भ की है, जिसके लिए उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जा रही है ताकि शिशु मृत्यु दर तथा मातृ मृत्यु दर का डाटा रखा जा सके।

अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) विनीत चौधरी ने सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों तथा सरकारी योजनाओं का बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक एच.आर.शर्मा, निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डा. बलदेव ठाकुर, निदेशक स्वास्थ्य सुरक्षा एवं नियामन रमन शर्मा तथा सभी कार्यक्रम अधिकारी व मुख्य चिकित्सा अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT
NOTICE INVITIGN TENDER

Sealed item rate tenders are hereby invited on Form 6&8 by theExecutive Engineer , Solan B&R Division H.P. PWD Solan (HP) of the Governor of Himachal Pradesh for the following works from the registered contractors of appropriate and class enlisted in HP PWD , whose registrations stood renewed as per revised instructions and also registered dealers under the Himachal Pradesh, General Sales Tax Act. 1968. The important dates of tender are as under :

Tender Schedule :

1. The last date for receipt of application for tender forms — 21.06.2016 upto 4:00 PM.
2. The Last date sale of tender forms. — 22.06.2016 up4:00 PM.
3. The Last date of Receipt of tender — 23.06.2016 upto 10:30 A.M.
4. The Last date of opening of Tender — 23.06.2016 11:00 A.M.

The tender shall be received upto 10:30 A.M. on 23.06.2016 and will be opened on the same day at 11:00 AM in the presence of intending contractors or their authorized representatives who may like to be present. The tender forms can be had from this office against cash payment as shown below (Non-Refundable0 during the working hour. The Earnest Money in the shape of National Saving Certificate time Deposit /Account /Saving account in any of the Post Office in HP. Duly pledged in favour of the Executive Engineer , (B&R) Division H.P. PWD Solan must accompany with each tender , conditional tenders and the tenders received without earnest money will simultaneously be rejected. The offer of the tender shall be kept open for 120 days. The Executive Engineer reserves the right to reject the tender without assigning any reason.

Sr. No.	Name of work	Estimated Cost Rs	Earnest Money	Time Limit	Cost of Tender
1.	Restoration of rain damages on Himani Hotel to ITI road Solan km 0/00 to 0/900 (SH: C/O wire creat wall along the Boundary of Mini Secretariat at Solan	7,15,622/-	15,000/-	Two Months	350/-

TERMS AND CONDTIONS:
1. The tender form will not be issued to those contractor whose performance has been unsatisfactory.
2. The contractor must have executed similar work successfully duing last 3 years.
3. Application without earnest money more will not be entertained
4. Contractor should have not more than to works in hand.

Adv. No.-0754/16-17 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक – बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक – जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार – ऋचा
अन्य सहयोगी
सुशील
रजनीश शर्मा
भारती शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

सभी जातियों व हर वर्ग के नवयुवको, नवयुवतियों, विदूर, विधवा व तलाकशुदा को योग्य जीवनसाथी मिलाने में निरन्तर सफलता हासिल कर रही प्रदेश की एकमात्र विश्वसनीय समाजसेवी संस्था द्वारा संचालित।

"आदर्श जोड़ी मैरिज ब्यूरो" पालमपुर केवल दस वर्षों में 8000 से अधिक जोडियां मिलाने का श्रेय प्राप्त कर चुकी है। हमारे पास हर प्रकार के रिश्ते उपलब्ध है। तथा उपलब्ध करवाये जाते है। जरूरतमन्द सम्पर्क करे :–

आदर्श जोड़ी मैरिज ब्यूरो
इन्द्रपुरी मार्किट नजदीक नया बस अड्डा पालमपुर
दूरभाष : 01894–230260 मोबाईल : 98163–22434

VAR - CHAHIYE

Suitable match for Choudhary Girl, 1984, 5'-3", BA. Fashion Design Course (Widow) 01894-230260, 98163-22434.
Suitable match for Choudhary Girl, 1982, 5'-2", MA. (English) B.Ed working as Lect.Govt.Job., 01894-230260, 98163-22434.
Suitable match for Rajput Girl,1989, 5'-4", B.Sc.MCA. working at Chandigarh.Rs. 25,000/- Pm. 01894-230260,98163-22434.
Suitable match for Rajput Girl, 1990, 5'-1", B.com. PGDCA Doing MBA.01894-230260, 98163-22434.
Suitable match for Choudhary Girl,1993, 5'-6",BCA., 01894-230260,98163-22434.
Suitable match for Rajput Girl,1991, 5'-7", B.Com. Diploma in Fashion Design, B.Sc (Fashion Design) working at Pvt.Job. 01894-230260, 98163-22434.
Suitable match for (Widow) Nai Girl, 1982, 5'-3",10+2, Radio graphy Tech, working at Govt. Job. (Upper Caste No bar) 01894-230260, 98163-22434.

VADHU - CHAHIYE :-

Suitable Match for Brahmin Boy, 1987, 5'-7", MBA., working at Chandigarh. Rs. 3.60 Lacs PA. 01894-230260, 98163-22434.
Suitable Match for Brahmin Boy,1984, 5'-9",Mass Communication Degree, working at Chandigarh. 01894-230260, 98163-22434.
Suitable Match for Brahmin Boy, 1983, 5'-9", MA.LLB.Working Advocate Himachal Court Shimla., 01894-230260, 98163-22434.
Suitable Match for Brahmin Boy, 1985, 6', BA. 1 1/2 Year's Diploma in H.M. working at Udaypur. Rs. 20,000 Pm. , 01894-230260, 98163-22434.
Suitable Match for Brahmin Boy, 1979, 5'-8", BA. Diploma (Make -up Artist) working at Mumbai., 01894-230260, 98163-22434.
Suitable Match for Khatri Boy,1986, 5'10", B.Sc. working own business., 01894-230260, 98163-22434.
Suitable Match for Choudhary Boy, 1988, 5'-8", M. Com.PGDCA working Pvt. Job Rs.18,000/-Pm. 01894-230260, 98163-22434.

Come ... Let Loose The Strings Of Your Senses, Know Your Potential & Excellence Through The Track of Sradesh!!

SWADESH ACADEMY

*BANK PO/CLERKS *SSC *HAS *CSAT *ENGLISH SPEAKING COURSE WITH PERSONALITY DEVELOPMENT * HPSSSB ALL EXAM * CTET * TET * UGC NET *JYOTISH CLASSES * CAREER GUIDANCE

YOGA CLASSES

6 TO +2 OF ALL SUBJECT

Commerce & Science All Subjects Collage Classes also

TUITION HOBBIES CLASSES: ☞MUSIC ☞DANCE ☞PAINTING ☞ACTING

NEAR UPPER CHAKKER CHOWK, SHIMLA, Mob. : 98163- 27534, 8679712387

मुख्यमंत्री ने जसवां परागपुर क्षेत्र को दी अनेक सौगातें

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कांगड़ा जिला के जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र में संसारपुर टैरेस के समीप जंदौर में एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए क्षेत्र के लोगों के कल्याण के लिए किए जा रहे विकास कार्यों में रोड़ा अटकाने के लिए स्थानीय विधायक की आलोचना की। उन्होंने कहा कि स्थानीय विधायक ने जंदौर में कालेज खोलने के विरोध में न्यायालय से रोक लगाई है। उन्हें स्थानीय ग्राम पंचायत प्रधान श्रेष्ठा देवी से सीख लेनी चाहिए, जिन्होंने कालेज के लिए भूमि दान की है, जिसका जसवां परागपुर के विधायक विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधायक इस मामले पर ओछी राजनीति कर रहे हैं, जो लोगों के हितों के विरूद्ध है।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि जंदौर में कालेज निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत होनी थी, जिससे बच्चों का लाभ होना था। लेकिन देर-सवेर क्षेत्र को कालेज अवश्य प्राप्त होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा नेताओं की कभी भी बड़ी सोच नही रही है और हमेशा ही झूठा प्रचार व घटिया राजनीति करते रहे हैं।

उन्होंने लोगों का आहवान किया कि ऐसे उम्मीदवारों को कभी भी वोट न दें, जो विकास कार्यों में अड़चने डालते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार क्षेत्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। पंचायतें को भी छोटे रास्तों व सड़कों का निर्माण का जिम्मा सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में 15,534 पाठशालाएं तथा 110 महाविद्यालय कार्यशील हैं।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ करने के प्रति सरकार प्रयासरत है। चम्बा, हमीरपुर तथा नाहन में तीन चिकित्सा महाविद्यालय खोले जा रहे हैं और प्रत्येक के लिए 189 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त बिलासपुर में एम्स खोला जा रहा है और मण्डी जिला के नेरचौक में ईएसआईसी कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मेडिकल कालेज एवं अस्पताल को अपने नियंत्रण में लिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने ये घोषणाए कीं:

* डाडासिबा में तहसील कल्याण कार्यालय खोलने की घोषणा।
* प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कस्बा कोटला से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोटला बैहल तक कोटला खड पर नए पुल का निर्माण।
* घमरौर बरनाली तथा बोहाला गांव के लिए अलग से पेयजल आपूर्ति योजना।
* डाडासिबा के लिए 25 हैंडपम्प स्थापित करने की घोषणा।
* जसवां परागपुर क्षेत्र के लिए सिचाई योजना की घोषणा, जिससे 3500 हैक्टेयर भूमि को सिचाई सुविधा उपलब्ध होगी और पौंग बांध से पानी उठाया जाएगा।
* कस्बा कोटला तहसील कार्यालय से बैरी वाया लखारड़ा-कानपुर सड़क की घोषणा।
* जंदौर और घुमी को जोड़ने वाले पुल तथा जंदौर-घुमी सम्पर्क सड़क का नाम कारगिल शहीद रमेश चन्द के नाम पर रखने की घोषणा।
* राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, जम्बाल में विज्ञान व वाणिज्य कक्षाएं आरम्भ करने की घोषणा।
* एक एक्सकेवेटर-कम-लोडर (जेसीबी) और रखरखाव के लिए एक करोड़ रुपये की घोषणा।
* प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कस्बा कोटला में रेडियोग्राफर का एक पद।
* राजकीय उच्च पाठशाला, रोड़ी-कोड़ी को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने की घोषणा।

उद्यमियों से प्रदेश में निवेश का आग्रह

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि सरकार सक्रियता एवं आक्रामकता से 'निमंत्रण द्वारा उद्योग' को अनुमति प्रदान कर रही है। हिमाचल ने उद्यमियों के लिए अधिक रास्ते खोले हैं और एक दिन आएगा जब हम हिमाचल ब्रांड के नाम से तथा 'हिमाचल में निर्मित' निशान सहित अंतरराष्ट्रीय बाजार में हिमाचली उत्पादों को देखेंगे।

वीरभद्र सिंह जिले के कसौली विधानसभा के दो दिवसीय दौरे के दौरान परवाणु में एक जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे। वीरभद्र सिंह ने कहा कि राज्य में नये निवेशों की शीघ्र स्वीकृतियां सुनिश्चित करने के लिए 'हिमाचल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट' की स्थापना की जा रही है ताकि राज्य में अधिक से अधिक व्यवसायिक घराने निवेश करें और यहां के युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हो। बागवानी, उद्योग तथा कृषि मुख्य क्षेत्र हैं जिन पर राज्य की आर्थिकी निर्भर करती है और ये क्षेत्र किसी भी राज्य की आर्थिकी के मुख्य मानक होने के साथ-साथ परोक्ष एवं अपरोक्ष रोजगार प्रदान कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षा ढांचे को सुदृढ़ करने के प्रयास कर रही है और सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान 36 राजकीय कॉलेजों के साथ-साथ 1289 स्कूल खोले हैं। आज राज्य में कॉलेजों की संख्या बढ़कर 110 हो गई है। राज्य के अनेक स्कूलों में व्यवसायिक पाठयक्रम शुरू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आधुनिक, बुनियादी एवं शिक्षण सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से 30 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के साथ 'मुख्यमंत्री आदर्श विद्यालय योजना' शुरू की गई है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक विधानसभा में दो वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं का चयन किया जाना है ताकि विद्यार्थी बदलती शिक्षा पद्धति के अनुरूप अपने आप को तैयार कर सकें। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र साक्षरता दर में केरल के बाद दूसरे स्थान पर है। वीरभद्र सिंह ने माध्यमिक पाठशाला नरयाणी, दतियार तथा करोल को उच्च विद्यालय और प्राथमिक पाठशाला टकसाल तथा कामली को माध्यमिक पाठशालाओं में स्तरोन्नत करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि उनके विरूद्ध विपक्ष द्वारा झूठे मामले बनाये जा रहे हैं, वे दावे के साथ कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री को इन मामलों में तथ्यों की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि एक ही समय में तीन जांच एजेंसियां उनके विरूद्ध एक आयकर मामले में जांच कर रही हैं जो देश के इतिहास में पहले कभी भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अंत में सत्य की ही जीत होगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी प्रधानमंत्री से इन मामलों के सम्बन्ध में बात नहीं की है।

हि.प्र. खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश चौहान ने मुख्यमंत्री से औद्योगिक क्षेत्रों के लिए संपर्क मार्गों के रखरखाव एवं सुदृढ़ीकरण तथा क्षेत्र के कुछ स्कूलों के स्तरोन्नयन के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। उन्होंने मौजूदा विधायक पर क्षेत्र के विकास की अनदेखी करने का आरोप लगाया। धगाड़ बाईपास पर पुल के निर्माण तथा ग्राम पंचायत जाबली में कोटी के लिए उठाउ जलापूर्ति योजना के निर्माण के लिए धनराशि की मांग की।

हि.प्र. कांग्रेस कमेटी के महासचिव विनोद सुलतानपुरी ने कहा कि क्षेत्र के वर्तमान विधायक ने विकास के मामले में परवाणु को हमेशा ही नजरअंदाज किया है। उन्होंने परवाणु को उप तहसील का दर्जा देने तथा परवाणु व साथ लगते क्षेत्रों के मौजूदा सड़कों के विकास के लिए 10 करोड़ रुपये की राशि का भी आग्रह किया।

HRTC परिचालक संघ एंव कौशल विकास भत्ता के अध्यक्ष की सयुंक्त समन्वय समिति के अध्यक्ष व सचिव को चेतावनी

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन परिचालक संघ एंव कौशल विकास भत्ता के अध्यक्ष ने सयुंक्त समन्वय समिति के अध्यक्ष पवन

गुलेरिया व सचिव नील कमल की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खडा किया है और कहा है कि मौजूद सयुंक्त सचिव सामान्य समिति जेसीसी कर्मचारियों की जायज मांगों जैसे अधिक समय भत्ता, पैंशन, जी पी एफ, भर्ती जैसे मुद्दों पर काम न करते हुए परिवहन मन्त्री के ब्यानों पर टिप्पणी कर रहे हैं जो कर्मचारी व निगम हित में नही है।

उन्होने कहा निगम के कर्मचारियों की किसी अधिकारी विशेष से या सरकार से व्यक्तिगत लडाई नही हैं। हमारी लडाई नितीगत, कर्मचारी तथा निगम हित की लडाई है। किसी श्रेणी व्यक्ति विशेष को नाजायज फायदा पहुंचाने की लडाई नही है। परिचालक संघ एंव कौशल विकास भत्ता के अध्यक्ष कुशाल झामटा ने कहा कि जे सी सी अपने संघर्ष की रूप रेखा तह करे अन्यथा हम इस सघर्ष का विरोध करेंगे।

परिचालक संघ एंव कौशल विकास भत्ता के अध्यक्ष ने कहा कि कौशल विकास भत्ते में कार्यरत परिचालकों को निगम में ही नियुक्ति का मौका दिया जाये। क्योंकि अब यह लोग परिचालक की डियूटी बखूबी निभा रहे है। इन परिचालकों से हिमाचल पथ परिवहन निगम को करोड़ो का लाभ मिल रहा है।

सरकार ने बढ़ाया कलाकारों का पारिश्रमिक भत्ता

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश में सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए अनुबन्धित किए जाने वाले लोक कलाकारों का पारिश्रमिक भत्ता बढ़ाने की अधिसूचना जारी की है। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि विभाग द्वारा सरकारी योजनाओं के प्रचार के लिए अनुबन्धित किए जाने वाले 11 सदस्यीय ए-ग्रेड दल का पारिश्रमिक 5600 रुपये से बढ़ाकर 7000 रुपये प्रति कार्यक्रम कर दिया है। उन्होंने बताया कि बी-ग्रेड दल का पारिश्रमिक 5875 रुपये और सी-ग्रेड दल का पारिश्रमिक भी बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा बढ़ाए गए दरों के अनुसार अब 10 सदस्यीय दल को 6475 रुपये, 8 सदस्यीय दल को 5425 रुपये तथा 4 सदस्यीय दल को 2530 रुपये प्रति कार्यक्रम के हिसाब से भुगतान किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि विभागीय नाटय दलों के साथ अनुबन्धित किए जाने वाले नैमितिक कलाकारों का दैनिक भत्ता 150 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये किया गया है, जबकि जिला स्तरीय प्रति कार्यक्रम के लिए एक कलाकार को 400 रुपये, राज्य स्तरीय कार्यक्रम के लिए 500 रुपये और अर्न्तराज्जीय स्तरीय कार्यक्रम के लिए 600 रुपये प्रति कार्यक्रम के हिसाब से पारिश्रमिक दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इससे सरकार की जन कल्याण नीतियों और विकास कार्यक्रमों का नुक्कड़ नाटकों और गीत संगीत के माध्यम से प्रचार करने के लिए अब अच्छे पारिश्रमिक के फलस्वरूप नामी एवं स्तरीय कलाकार सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के साथ जुड़ पाएंगे।

प्रदेश सरकार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के सुदृढ़ीकरण के लिए कृत संकल्प

शिमला/शैल। राज्य सरकार हि.प्र. चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर के डा.जी.सी. नेगी पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विभाग में भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के मानदंडों के आधार पर 86 पद स्वीकृत हैं।

प्रदेश सरकार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के सुदृढ़ीकरण के लिए कृत संकल्प है ताकि राज्य के किसानों को समुचित लाभ प्राप्त हो। वर्तमान में विभाग में 51 संकाय पद भरे हुए हैं जबकि सहायक प्रोफेसरों के 10 पदों को भरने की विज्ञापन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसके अतिरिक्त 12 और पदों को भरने की प्रक्रिया भी जारी है।

केन्द्र ने मण्डी जलापूर्ति परियोजना के लिये 41.09 करोड़ की किश्त जारी की

शिमला/शैल। केन्द्र सरकार ने मण्डी जलापूर्ति परियोजना के लिये 41 करोड़ नौ लाख 15 हजार रुपये की केन्द्रीय सहायता की अंतिम किश्त जारी कर दी है। यह राशि जवाहर लाल नेहरु शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत छोटे एवं मध्यम शहरों के लिये शहरी अधोसंरचना विकास योजना (यूआईडीएसएसएमटी) के लिये जारी की गई है।

शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने इस आशय की जानकारी देते हुए कहा कि यह राज्य की सबसे बड़ी जलापूर्ति योजना है, जो योजना के लाभार्थियों को चौबीस घण्टे पानी की आपूर्ति सुनिश्चित बनाएगी।

उन्होंने कहा कि यह राज्य की महत्वकांक्षी परियोजनाओं में से है तथा इसका निर्माण तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा।

जब तक गलती करने की स्वतंत्रता ना हो तब तक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नही है। .....महात्मा गांधी

सम्पादकीय

मोदी के दो वर्ष

प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदी की सरकार को सत्ता में आये दो वर्ष का समय हो गया है। सरकार की सफलता/असफलता के आकलन के लिये यह पर्याप्त समय माना जा रहा है। क्योंकि भाजपा पहले भी केन्द्र में सत्ता में रह चुकी है। कई बड़े राज्यों में उसकी सरकारें है। मोदी स्वयं पन्द्रह वर्ष तक गुजरात के मुख्य मंत्री रह चुके है फिर 2014 के लोकसभा चुनावों में मोदी ने देश की जनता से साठ महीने का समय सरकार के लिये मांगा था। इस सबको सामने रखते हुए सरकार का एक निष्पक्ष आकलन बनता है। 2014 के चुनावों से पहले यू पी ए सरकार के खिलाफ सबसे बडा आरोप भ्रष्टाचार का था जनता में रामदेव और अन्ना के आन्दोलनों से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा आक्रोश उभरा और उस आक्रोश में मोदी जनता की उम्मीदों के केन्द्र बन गये थे। लेकिन दो वर्ष के समय में यू पी ए शासन के खिलाफ भ्रष्टाचार के किसी भी मामलें में कोई ठोस कारवाई अब तक सामने नही आई है। मोदी यह दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई मामला सामने नही आया है। लेकिन यहां प्रधानमंत्री को यह मानना होगा कि क्या वह अपनी राज्य सरकारों के बारे में भी ईमानदारी से यह दावा कर सकते हैं? केन्द्र में आज भ्रष्टाचार है या नही इसका पता आने वाले समय में लगेगा। प्रधानमन्त्री का यह दावा कि एल ई डी बल्बों, कैरोसीन तेल और फर्जी राशन कार्ड, फर्जी अध्यापक आदि काण्डों में लाख करोड़ से अधिक का पर्दाफाश करके इतने धन को बचा लिया गया है। प्रधानमन्त्री का यह दावा सही हो सकता है लेकिन इसी के साथ यह सवाल भी उठता है कि इस भ्रष्टाचार के लिये किसे सजा दी गयी? क्या घपला सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों में ही हुआ है या भाजपा शासित राज्यों में भी फर्जी राशन कार्ड पाये गये? प्रधानमंत्री ने आधार कार्ड के साथ लिंक करके लाभार्थी को सीधा लाभ पहुंचाने का भी दावा किया है लेकिन मोदी जी को यह भी स्मरण रखना होगा कि यू पी ए शासन काल में इसी योजना पर भाजपा का विरोध कितना था। फिर इन सब दावों से इस सच्चाई को भी नजर अन्दाज नही किया जा सकता कि आज खाद्य पदार्थों की कीमतें पहले से ज्यादा बढ़ गयी है और इस मंहगाई को किसी भी गणित से नजर अन्दाज नही किया जा सकता ।

प्रधानमन्त्री ने इन दो वर्षो में जितनी विदेश यात्राएं की हैं और इन यात्राओं में जितने आपसी समझौते हुए हैं उनसे आम आदमी को कितना लाभ अब तक मिल पाया है। इसको लेकर कोई दावा अब तक सामने नहीं आया है। काले धन का मसला अपनी जगह पहले की तरह ही खड़ा है। यह सही है कि इन विदेश यात्राओं में प्रधानमन्त्री जंहा भी गये हैं वहां रह रहे प्रवासी भारतीयों में उनको लेकर बड़ा उत्साह देखने को मिला है लेकिन आज भारत से बाहर रह रहे भारतीयों का प्रतिशत कितना है? देश की कुल आबादी के एक प्रतिशत से अधिक नही है। ऐसे में क्या सारी योजनाओं का केन्द्र केवल एक प्रतिशत लोगों को ही मान लिया जाना चाहिए? अभी तक मोदी सरकार ने जितनी भी विकास योजनाओं का चित्र देश के सामने रखा है उसका प्रत्यक्ष लाभ पांच प्रतिशत से अधिक के लिये नही है। प्रधानमंत्री ने स्वयं माना है कि गरीब आदमी को जो दो तीन रूपये किलो सस्ता अनाज मिल रहा है। उसमें 27 रूपये प्रति किलो की सब्सिडी केन्द्र सरकार दे रही है लेकिन यह जो 27 रूपये दिये जा रहे है यह धन कहां से आ रहा है? फिर सरकार यह 27 रूपये तो उस व्यापारी को दे रही है जो इस राशन की सप्लाई कर रहा है। इसी राशन में फर्जी बाडा भी हो रहा है। इसलिये इस व्यवस्था से किसी को भी लाभ नही हो रहा है न सरकार को और न ही अन्न उगाने वाले किसान का। इसलिये आज इतना बड़ा जन समर्थन हासिल करने के बाद मोदी सरकार सरकार को इस संभ में अब तक जितनी भी योजनाएं आम आदमी के नाम पर आयी हैं उनका सीधा लाभ बड़े व्यापारी को ही हुआ है। क्योंकि वह हर योजना में सप्लायर की भूमिका में रहा है। इसलिये यदि मोदी सरकार इस सप्लायर के चगुंल से आम आदमी को बचाने का प्रयास करती है तभी वह सफल हो पायेगी। शहरों के नाम बदलने उनको स्मार्ट बनाने और स्कूली पाठयक्रमों में कुछ बदलाव करके केवल समाज के अन्दर एक अलग तरह का तनाव पैदा किया जा सकता है लेकिन उससे आम आदमी का कोई स्थायी लाभ होने वाला नही है इसलिये अभी मोदी सरकार को व्यापक सद्भंर्भो में सफल करार नही दिया जा सकता ।

प्रदेश सरकार भारतीय औषधि पद्धति को बढ़ावा दे रही है

भारतीय औषधि पद्धति (आईएसएम) राज्य में गुणात्मक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने में अहम भूमिका निभा रही है। बिना किसी दुष्प्रभाव के यह पद्धति भारत में सदियों से प्रचलित है, जिसका उपयोग प्राचीन काल में ऋषि–मुनि भी करते रहे, जिसका अनुसरण विदेशों में भी किया जा रहा है। राज्य सरकार प्रदेश में आयुष चिकित्सा पद्धति को अधिक प्रचलित करने के लिए प्रदेश में कार्यरत आयुर्वेदिक संस्थानों को सदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है।

वर्तमान में राज्य में लोगों को 1112 आयुर्वेदिक स्वास्थ्य संस्थानों, 32 आयुष अस्पतालों, 14 होम्योपैथी स्वास्थ्य केन्द्रों, तीन यूनानी स्वास्थ्य केन्द्रों तथा चार आमची क्लिनिकों के माध्यम से चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

आयुर्वेद विभाग को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सरकार ने लोगों

को सुविधा प्रदान करने के लिए 83 आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की है। एक प्रयोगशाला सहायक तथा 10 स्टाफ नर्सों की नियुक्ति भी की गई है। कांगडा जिले के अप्पर मझेलटी के आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र को 10 बिस्तरों के आयुर्वेदिक अस्पताल में स्तरोन्नत किया है तथा इसके लिये आठ पदों का सृजन भी किया है।

राज्य सरकार आयुर्वेदिक संस्थानों में ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिये भी कृतसंकल्प है। राजीव गान्धी स्नात्कोत्तर आयुर्वेदिक कालेज में अतिरिक्त दो प्रवक्ताओं की नियुक्ति की गई है। राज्य में एक होम्योपैथी कालेज, बी फार्मासियूटिकल कालेज जोगेन्द्रनगर, कांगडा के पपरोला तथा सिरमौर के माजरा में तीन राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसियां कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त, जोगेन्द्रनगर में एक दवाई परीक्षण प्रयोगशाला तथा मण्डी के जोगेन्द्रनगर, हमीरपुर के नेरी, शिमला के धमरेडा तथा बिलासपुर जिले के झलेड़ा में चार हर्बल गार्डन स्थापित किये गए हैं।

लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए विभाग की सभी क्रियात्मक पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जा रहा है। कांगड़ा जिला के अपर मझेटली आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र को 10 बिस्तरों वाले आयर्वेदिक अस्पताल में स्तरोन्नत किया गया है। इसके अलावा इस संस्थान के लिए विभिन्न वर्गों के 8 पदों को सृजित किया गया है।

प्रदेश सरकार इस चिकित्सा पद्धति को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रशिक्षण व विस्तार गतिविधियों को आगे बढ़ा रही है। प्रदेश सरकार मण्डी जिले के जोगेन्द्रनगर स्थित आईएसएम में प्रशिक्षण व्यवस्था के साथ साथ विस्तार गतिविधियों को भी बढ़ावा दे रही है। संस्थान ने 34 प्रशिक्षण शिविर एवं अन्य विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से 462 विद्यार्थियों और 547 किसानों को लाभान्वित किया है।

वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य सरकार ने 43,65,587 रोगियों का सामान्य चिकित्सा उपचार, 23,893 रोगियों का पंचकर्मा तथा 19,224 रोगियों का क्षारसूत्र करवाया है। काया–चिकित्सा, आर्थो, शल्य तथा शालक्य तन्त्र विशेषज्ञों द्वारा राज्य के दूर–दराज के क्षेत्रों पूह, सांगला और रिकांगपिओ में बहु–उद्देशीय शिविरों का आयोजन किया गया। गत वर्ष कुल्लू दशहरा के दौरान मैडीसिन, सर्जरी, आंख, नाक व कान, प्रसूति तन्त्र, स्त्री रोग, योग, नैचरोपैथी व क्षारसूत्र विशेषज्ञ शिविरों का आयोजन भी किया गया। इसके अतिरिक्त, हर्बल मेडिसिनल पौधों की प्रदर्शनी भी लगाई गई।

शिमला जिले के रोहडू उपमण्डल के समोली, चिढ़गांव, चपोति में क्षारसूत्र (पाईलज), तिब्बियन पद्धति सोवा–रिग्पा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी तथा आयुर्वेद विशेषज्ञ उपचार बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन किया गया। इसके अलावा, आउटरीच स्वास्थ्य गतिविधियों के अन्तर्गत कांगड़ा जिले के गुलेर, बडाल, थोर, गलौर तथा आयुर्वेद अस्पताल देहर में मडिसिन, आर्थो, स्त्री रोग, पंचकर्मा, आंख, कान व नाक इत्यादि के विशेषज्ञ उपचार शिविर भी इस अवधि के दौरान आयोजित किए गए।

प्रदेश सरकार द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति के प्रति सक्रिय पहल, से प्रदेश में लोगों के उनके घरद्वार पर बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

अति सजग रहना होगा बचत योजनाएं में निवेश करते समय

एक आम भारतीय अपने जीवन में बचत को बहुत महत्व देता है। वह अपने जीवन में आने वाले हर छोटे – बडे खर्चे का हिसाब – किताब और तदनुसार संचय की गणना कहीं न कहीं अपने जहन में अवश्य रखता है। समय समय पर वह इसके लिए दूसरों से सलाह मशवरा भी करता है। मगर दुर्भाग्य से उसे बचत योजनाओं की सही जानकारी न होने के कारण वह अपने गाढे पसीने की कमाई का सदुपयोग नहीं कर पाता है। दूसरी ओर देखा गया है कि वित्तीय कम्पनियां एवं उनके अभिकर्ता अपना लक्ष्य (Target) पूरा करने के लिए किसी की भी कमाई को अनुचित स्थान पर निवेश करने में कतई नहीं हिचकिचाते, क्योंकि यह उनके अस्तित्व का सवाल होता है। आज बाजार में सैकड़ों बचत योजनायें विद्यमान हैं, जो निवेशकर्ताओं को उनकी आवश्यकतानुसार सुविधाएँ प्रदान कराती हैं। मगर किस योजना में, कब और कितना पैसा निवेश किया जाये, यह बड़ा ही टेढ़ा सवाल है और इसका जवाब व्यक्ति विशेष और समयविशेष पर निर्भर करता है। वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से ही हमें आगामी वित्तीय वर्ष की आय, खर्च और बचत पर ध्यान देना चाहिये। ताकि वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए हम भविष्य को आर्थिक सुरक्षा दे सकें। एक सामान्य गणना के अनुसार व्यक्ति के लिए अपनी सकल आय के 33% भाग की बचत करना एक सुरक्षित भविष्य के लिए आवश्यक माना जाता है। निवेशकर्ता के लिए किसी भी योजना में अपना पैसा निवेश करते समय बहुत सी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है।

डा0. महेश कुमार वर्मा
प्रबंधक (भू – विज्ञान), NMDC Limited

विभिन्नता (Diversity): आपकी बचत विभिन्नता लिए (Diversified) होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि आपको अपना पैसा विभिन्न प्रकार की योजनाओं में एवं विभिन्न प्रकार से निवेश करना चाहिए। क्योंकि हर योजना में लाभ – हानि दोनों की ही संभावनाएं होती हैं। निवेशकर्ता के लिए आवश्यक है कि वह अपना कुछ पैसा बैंक योजनाओं में, कुछ बीमा योजनाओं में, कुछ जमीन – जायदाद में, कुछ सोने के रूप में तो कुछ मुचुअल फंड्स के रूप में सुरक्षित करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारा निवेश केवल जमीन – जायदाद में ही हो रहा है या फिर सोना ही सोना खरीदा जा रहा है, ऐसा करना भविष्य के लिए असुरक्षित हो सकता है।

द्रव्यता (Liquidity): एक ध्यान रखने योग्य बात यह है कि आपके निवेश किये गए पैसे की द्रव्यता (Liquidity) क्या है? क्या वह पैसा आपकी आवश्यकता के समय आपको मिलेगा? उदाहरण के लिए सुकन्या समृधि योजना का पैसा आपकी बेटी की 18 साल और 21 साल की उम्र पर ही मिलेगा, इससे पहले नहीं। जबकि लोक भविष्य निधि (PPF) का जमा पैसा 6ठे साल पूरे होने के उपरांत हर वर्ष कुछ हद तक आहरण (Withdraw) किया जा सकता है। कुछ योजनाओं का पैसा 15 या 20 वर्ष की लम्बी अवधि के उपरान्त आहरण होता है, जब वह हमारे उतना उपयोगी नहीं रहता है, जिसके लिए आज मुश्किल से बचत की जा रही है। इसलिए बचत योजना इस प्रकार की लेनी चाहिए कि आवश्यकता के समय पैसा उपलब्ध भी हो सके। 15 – 20 या उससे अधिक वर्षों की लम्बी अवधि के लिए अपना पैसा निवेश करना श्रेयस्कर नहीं है, लेकिन हाँ, सरकारी योजनायें जैसे लोक भविष्य निधि, सुकन्या समृधि योजना, पेंशन योजनायें इसके अपवाद माने जा सकते हैं, जहाँ पर आपको लम्बी अवधि के लिए ही अपना पैसा निवेश करना पड़ेगा।

माना जाता है कि जमीन जायदाद (Real Estate) के निवेश में बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलता है, परन्तु इसकी लिक्विडिटी बहुत ही कम होती है, अगर आपके बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए आपको 5 लाख रूपयों की आवश्यकता है तो 25 लाख रूपयों के कीमत की जमीन बेचना नासमझी मानी जायेगी। इसके लिए आपको बच्चे के जन्म से ही योजना बनानी पड़ेगी।

प्रतिलाभ (Return): निवेश किये गए पैसे का प्रतिलाभ कितने प्रतिशत के हिसाब से मिलेगा? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कई निजी वित्तीय कम्पनियां बहुत आकर्षक रिटर्न देती हैं अर्थात 12% वार्षिक से भी अधिक ब्याज दर, परन्तु अपने निवेश को सुरक्षित बनाने के लिए उस वित्तीय कम्पनी का इतिहास एवं उसके बारे में अच्छी तरह जान लेना चाहिए। कहीं

ऐसा ना हो कि आपके साथ कोई धोखा – धड़ी का मामला हो जाये।

परिपक्वता मूल्य (Maturity Value): मान लीजिये किसी योजना में आपने आज पैसा निवेश किया जो कि 20 वर्ष की अवधि के उपरान्त आपको आकर्षक अच्छा रिटर्न देगी। मगर क्या वह पैसा आपकी उस समय की आवश्यकता पूरी करेगा, जिस हिसाब से महंगाई की दर बढ रही है? इसके लिए आज से 20 वर्ष पहले का परिदृश्य देखें, जब कितनी कम आय में लोग क्या क्या काम कर लेते थे। इसके विपरीत अगले 20 वर्ष में महंगाई भी बढ़ेगी ओर साथ ही खर्च करने के अवसर भी कई गुणा बढ जायेंगे। 20 वर्ष के उपरान्त जो आपको एक लाख रुपये की राशि मिलेगी, उसका मूल्य आज के 20,000 रूपये के बराबर ही रह जायेगा। 15 या 20 वर्ष की लम्बी अवधि के उपरान्त परिपक्वता पर उस राशि का मूल्य कितना रहेगा, यह जानना आवश्यक है। इसके लिए इन्टरनेट पर कई प्रकार के कैलकुलेटर उपलब्ध हैं।

बचत बनाम बीमा (Saving V/s Insurance): एक बहुत ही साधारण सा प्रश्न है कि आपको बचत की आवश्यकता है या बीमा की। क्योंकि जहाँ बीमा है वहां यहाँ बचत पर बहुत ही कम ही रिटर्न मिलेगा। समझने की बात ये है कि बीमा हमेशा कमाने वाले और घर के मुखिया व्यक्ति का होता है, ताकि अगर दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो पत्नी ओर बच्चों को आर्थिक सहायता मिल सके। अपनी गृहणी पत्नी या बच्चों के नाम पर बीमा कभी न करवाएं। अगर आपके पास अच्छी संपत्ति, जमीन, जायदाद या अच्छा बैंक बैलेंस है तो अपना पैसा बीमा योजनाओं में निवेश ना ही करें तो अच्छा रहेगा।

बाज़ार लिंक्ड योजनायें (Market Linked Scheme): बाजार से लिंक्ड योजनाओं में पैसा उसी सूरत में निवेश करना चाहिए जब आपको बाजार को ट्रैक करने के सही ज्ञान हो और अपने खाते को Maintain करने का भी सही ज्ञान हो। अन्यथा अधिकतर निवेशकर्ता कम समय में अधिक रिटर्न प्राप्त करने के चक्कर में बाजार से लिंक्ड योजनाओं में नुकसान ही प्राप्त करते हैं। जिन निवेशकर्ताओं को बाजार का ज्ञान नहीं है और बाजार से लिंक्ड योजनाओं में निवेश करना पड़ रहा है, उन्हें सरकारी योजनाओं (Government Securities) में निवेश करना चाहिए, जहाँ पर 'कम रिस्क: कम लाभ' के अवसर होते हैं। वहां पैसा अधिक सुरक्षित माना जा सकता है, बजाय 'अधिक रिस्क: अधिक लाभ' के।

टैक्स का चक्कर (Tax Liability): टैक्स बचत के लिए आज बाजार में अनेक बचत योजनायें हैं, मगर यह ध्यान रखना चाहिए कि सभी योजनाओं को मिलाकर कुल रू.1. 5 लाख पर ही टैक्स का लाभ मिलेगा। हाँ, अभी भारत सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना में निवेश पर रू. 50,000 का अतिरिक्त टैक्स लाभ प्रदान किया है, जो सराहनीय है। इसका लाभ प्रत्येक निवेशकर्ता के लिए अनुशन्सित है। अच्छा रिटर्न वह माना जाता है जो कर – मुक्त (Tax-Free) हो, अर्थात परिपक्वता पर मिली संपूर्ण राशि कर – मुक्त होनी चाहिए। ऊँची ब्याज दर पाने के बाद आपको उस पर कर चुकाना पड़े तो क्या लाभ? और अगर ब्याज पर कर नहीं चुकाया तो वह काला धन माना जायेगा। संपूर्ण बचत केवल अपने नाम ही न करके उसे पत्नी व बच्चों के नाम बाँट दें तो उस पर मिले ब्याज पर आपको टैक्स बचाने में काफी मदद मिल सकती है। LIC की बहुत सी योजनायें कर – मुक्त परिपक्वता राशि देती हैं। भारत सरकार की लोक भविष्य निधि, सुकन्या समृधि योजना आदि भी कर – मुक्त परिपक्वता राशि देती हैं।

गृह ऋण (Home Loan): आजकल निरन्तर आय वाले किसी भी व्यक्ति को वित्तीय कम्पनियां गृह ऋण देने के लिए सदैव तत्पर हैं। गृह ऋण भी निवेश का श्रेष्ट साधन माना गया है। इसमे केवल 10 से 12% वार्षिक ब्याज दर पर ऋण पाकर आप एक अच्छी अचल संपत्ति के मालिक बन सकते है, जिसका मूल्य बाजार में उपलब्ध सभी योजनाओं से तीव्र गति से बढेगा। इसके अन्य दो लाभ इस प्रकार से हैं कि एक तो फ्लैट आदि हेतु लिए गए ऋण पर दिए गए सालाना ब्याज पर टैक्स छूट मिलेगी और साथ ही दूसरा उसी फ्लैट को किराये पर देकर मासिक किश्त में आपको काफी हद तक मदद मिलेगी। गृह ऋण लेते वक्त हस्ताक्षर के लिए दिए सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ कर ही हस्ताक्षर करें, कोई शंका होने पर कम्पनी से अवश्य पूँछें। एक साधारण सी गणना के अनुसार रू 20 लाख के, 20 वर्ष की अवधि के लिए गए गृह ऋण पर लगभग 10% वार्षिक ब्याज दर के आधार पर लगभग रू 20,000 मासिक किश्त (EMI) आयेगी। अपने गृह ऋण का बीमा करवाएं तो अच्छा रहेगा, अर्थात अगर 20 वर्षों की ऋण की अवधि में ऋण चुकाने वाले की मृत्यु हो जाती है तो बाकि किश्तें माफ। इसके लिए आपको कुछ हजार रूपयों का अतिरिक्त ऋण लेना होता है, जो कि मासिक आसान किश्तों के साथ ही जमा भी हो जाता है, दूसरी तरफ आपका ऋण 20 वर्षों के लिए सुरक्षित हो जायेगा। गृह ऋण की अवधि में कभी कभी रू. 50,000 या 100,000 अग्रिम अर्थात मासिक किस्तों के आलावा जमा करवायें तो वह राशि मूल रकम में से कम हो जाएगी और आपकी ऋण की अवधि कम होती चली जाएगी। ऐसा करके आप एक बड़ी बचत कर सकते हैं। अग्रिम जमा करवाने के लिए कुछ बैंक बहुत ही नाम मात्र के शुल्क भी वसूल करते हैं।

अभीकर्ता बनाम गणक (Agent Vs Calculator): किसी भी बचत, बीमा या अन्य योजना में निवेश करने से पहले आप अभिकर्ता (Agent) की बातों में आने के बजाय, स्वयं उस योजना का वाउचर पढ़ें या इन्टरनेट पर उसके बारे में गहन अध्ययन करें। अभिकर्ता को कभी भी नकद राशि या उसके नाम का चैक न देकर कम्पनी के नाम का ही चैक दें। अभिकर्ता द्वारा पैसे खाने के मामले भारत में बहुत आम हैं। प्राय: देखा गया है कि अभिकर्ता अपनी नौकरी बचाने, अधिक कमीशन बनाने और अपना लक्ष्य (Target) पूरा करने के लिए निवेशकर्ता को बेवकूफ बनाने में तनिक भी नहीं हिचकिचाते। उदाहरण के तौर पर वे कहेंगे कि प्रतिवर्ष 1 लाख रूपये जमा करने पर 10 वर्ष में आपके 10 लाख रूपये जमा होंगे, जबकि हकीकत यह है कि 8% वार्षिक ब्याज दर की गणना के अनुसार कम्पनी के पास आपके 15,64,000 रूपये जमा हो जायेंगे। आजकल इन्टरनेट पर किसी भी योजना का सम्पूर्ण विवरण, तुलनात्मक अध्ययन, लाभ – हानि की संभावनाएँ, यहाँ तक कि योजना का कैलकुलेटर भी दिया होता है, जो आपके निवेश की सटीक गणना उपलब्ध कराता है। अपनी आय, निवेश का उद्देश्य आदि के सही अनुकूलन के अनुसार ही योजना में पैसा निवेश करें। श्रेष्ट तो यह रहेगा की अभिकर्ता के बजाय आप स्वयं ही कम्पनी के साथ सम्बन्ध बनाकर निवेश करें। योजना के बारे में कम्पनी के किसी बड़े और अनुभवी अधिकारी से स्वयं बातचीत करें। कम्पनी के साथ सीधा निवेश करने पर अभिकर्ता का लाभ सीधे आपको भी मिल सकता है।

मंत्रिमण्डल के निर्णय

अवैध कब्जों पर निर्मित भवन नही होंगे नियमित

शिमला।हि.प्र. मंत्रिमण्डल की बैठक में नगर नियोजन तथा अन्य स्थानीय निकायों में भवन मालिकों द्वारा किए गए विचलन को 'जैसा है, जहां है' के आधार पर एक अध्यादेश के माध्यम से नियमित करने की मंजूरी प्रदान की। वशर्ते सैट बैक की आवश्यकतानुसार 30 प्रतिशत स्थान खुला हो।

मंत्रिमण्डल की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने की।

अध्यादेश की घोषणा के उपरान्त अवेदकों को 45 दिनों के भीतर आवेदन करना होगा। नगरपालिका की भूमि अथवा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों पर निर्मित भवनों को नियमित नही किया जाएगा। ऐसे सभी अवैध निर्माणों की गहनता से जांच की जाएगी। अध्यादेश के अन्तर्गत नियमितिकरण से वंचित भवनों के बिजली व पानी के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। बैठक में निर्णय लिया गया कि ग्रीन बैल्टस की अधिसूचना के उपरान्त हरित क्षेत्रों में किए गए अवैध निर्माणों को नियमित नही किया जाएगा।

हि.प्र. टीसीपी अधिनियम 1977 का यह संशोधन अवैध निर्माणों को नियमित करने का अन्तिम अवसर है। विभाग को भविष्य में किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण की अनुमति न देने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।

आवासीय भवनों (जहां अनुमति प्राप्त की गई हो, लेकिन सैट बैक पर डेविएशन किया गया है), के लिए सेट बैक पर 35 प्रतिशत तक डेविएशन के लिए दर धरातल स्तर पर 800 रुपये प्रति वर्ग मीटर तथा इसके उपरान्त हर मंजिल के लिए 400 रुपये की दर निर्धारित की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों अथवा नगरपालिका के बाहर के क्षेत्रों में अवैध भवनों के लिए धरातल स्तर की कवरेज के लिए निर्धारित दर 400 रुपये प्रति वर्ग मीटर जबकि इसके बाद प्रत्येक मंजिल के लिए 200 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी। सैट बैक पर 35 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक डेविएशन के लिए निर्धारित दरें दोगुणा होंगी।

व्यावसायिक अनाधिकृत संरचनाओं के लिए यह कम्पाऊंडिग दर दो गुणा होगी।

नगरपालिका क्षेत्रों में अनाधिकृत मंजिलों की संख्या 100 वर्ग मीटर अनाधिकृत क्षेत्र तक 1500 रुपये प्रति वर्ग मीटर रखी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में डेविएशन के लिए यह दर एक हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी। अनाधिकृत मंजिलों में 100 वर्ग मीटर से अधिक के डेविएशन की दर दो गुणा होगी।

मंत्रिमण्डल ने शिक्षा विभाग में अंशकालीन कर्मियों का मानदेय प्रथम अप्रैल, 2016 से 1700 रुपये से बढ़ाकर 1900 रुपये करने को भी मंजूरी प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने चम्बा जिले के डलहौजी नगर परिषद क्षेत्र में जिन लोगों को स्वतंत्रता से पूर्व पट्टे पर भूमि दी गई थी, को मालिकाना हक देने के लिए नीति बनाने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में शिक्षा विभाग में संयुक्त निदेशक के नेतृत्व में एक नया निरीक्षण प्रकोष्ठ सृजित करने का निर्णय लिया गया।

उच्च शिक्षा निदेशालय में उप-निदेशक स्कूल शिक्षा के एक पद को स्तरोन्नत कर संयुक्त निदेशक बनाने को स्वीकृति दी गई। इसके अतिरिक्त, उप-निदेशक (निरीक्षण) के 12 पद, 20 प्रधानाचार्य (निरीक्षण) तथा 20 खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी (निरीक्षण) के पद सृजित किए जाएंगे।

बैठक में वर्ष 2016 के दौरान विधायन योग्य आम प्रापण के लिए मण्डी मध्यस्थता योजना को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया। इस योजना के अन्तर्गत 300 मीट्रिक टन गुठलीदार और 200 मीट्रिक टन कलमी आम की खरीद क्रमशः 5.50 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 6.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से की जाएगी। प्रापण का कार्य एचपीएमसी तथा हिमफैड द्वारा 34 फल एकत्रिकरण केन्द्रों के माध्यम से किया जाएगा। दोनों एजेंसियों को 1.30 रुपये प्रति किलोग्राम हैंडललग चार्जिज की वसूली करने की अनुमति होगी।

योजना के अन्तर्गत प्रापण तथा हैंडलिंग के दौरान परिवहन क्षति को ध्यान में रखते हुए किसानों व बागवानों से 2.5 प्रतिशत (भार) अधिक फलों का प्रापण किया जाएगा। यह योजना प्रथम जुलाई से 15 अगस्त, 2016 तक कार्यान्वित की जाएगी।

मंत्रिमण्डल ने राज्य की जल विद्युत नीति में कुछ संशोधन करने को मंजूरी दी। जिन मूल हिमाचलियों को दो मैगावाट क्षमता तक की परियोजनाएं आवंटित की जाती है, सरकार परियोजना के आवंटन तथा परियोजना आरम्भ होने के दो वर्ष के उपरान्त पूर्ण विनिवेश की किसी भी अवस्था के दौरान प्रमोटरों द्वारा 49 प्रतिशत इक्विटी शेयर को बेचने अथवा हस्तांतरण के आवेदन पर विचार कर सकती है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि मूल हिमाचलियों, जिन्हें दो मैगावाट से पांच मैगावाट क्षमता की परियोजनाएं आवंटित की जाती हैं, सरकार परियोजना के आरम्भ होने के दो वर्ष उपरान्त पूरे विनिवेश तथा परियोजना के आंवटन के बाद किसी भी चरण में गैर हिमाचलियों को 51 प्रतिशत इक्विटी शेयर को बेचने अथवा हस्तांतरित करने के प्रमोटर के आवेदन पर विचार कर सकती है।

बैठक में किन्नौर जिले में कडछम-वांगतू जल विद्युत परियोजना के निर्माण/स्थापना के लिए मैसर्ज जय प्रकाश पावर वैंचर लिमिटेड को पट्टे पर भूमि प्रदान काने को मंजूरी दी गई।

स्वास्थ्य क्षेत्र

* मंत्रिमण्डल ने स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय के अन्तर्गत सामान्य ड्यिूटी चिकित्सा अधिकारियों की सेवा निवृति आयु को बढ़ाकर 60 वर्ष करने का निर्णय लिया।

* स्वास्थ्य विभाग में समस्त पात्र चिकित्सा अधिकारियों को विभागीय परीक्षा पास करने की शर्त में छूट प्रदान करते हुए 4-9-14 पे स्केल प्रदान करने को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

* जनजातीय तथा दुर्गम क्षेत्रों (काजा व केलंग) के लोगों को विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से मंत्रिमण्डल ने अपोलो अस्पताल इंटरप्राईज लिमिटेड के साथ एक वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध बढ़ाने को मंजूरी प्रदान की।

* मंत्रिमण्डल ने 150 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल पालमपुर को स्तरोन्नत कर 200 बिस्तरों का अस्पताल बनाने को मंजूरी दी।

* बैठक में बिलासपुर जिले में कबीर पंथी बस्ती तथा बल्ही मरेटा में स्वास्थ्य उप-केन्द्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई।

* कांगड़ा जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रकड़ तथा पीर सलुही को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने का निर्णय भी बैठक में लिया गया।

* हमीरपुर जिले के रैल तथा फाल में वांछित स्टाफ सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का भी निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने जांगी-थोपन (480 मैगावाट) तथा थोपन पवारी (960 मैगावाट) की जल विद्युत परियोजनाओं के लैटर आफ इंटेंट की वैद्यता बढ़ाने का निर्णय लिया। बैठक में 104 मैगावाट की तांदी तथा 130 मैगावाट की राशिल जल विद्युत परियोजनाओं के आवंटन का निर्णय भी लिया गया।

बैठक में हिम ऊर्जा की संतुतियों के आधार पर पात्र आवेदकों को दो मैगावाट से पांच मैगावाट क्षमता की 24 जल विद्युत परियोजनाओं के आवंटन की भी स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने शिमला जिले के डुमैहर तथा मण्डी जिले की थुनाग तहसील की ग्राम पंचायत कलहानी तथा पदर तहसील की ग्राम पंचायत मढ़ में नए पटवार वृत सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में कांगड़ा जिले के फतेहपुर में नया सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मण्डल सृजित करने तथा आईपीएच उपमण्डल धीरा के अन्तर्गत ब्रंग में नया सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य अनुभाग खोलने का निर्णय भी लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने लोक निर्माण विभाग मण्डल नम्बर-1 मण्डी के अन्तर्गत झलटगरी में लोक निर्माण विभाग का नया उपमण्डल खोलने को भी मंजूरी प्रदान की।

शिक्षा क्षेत्र

* मंत्रिमण्डल ने सोलन जिले के राजकीय महाविद्यालय नालागढ़ में स्नातकोत्तर (रासायन विज्ञान) की कक्षाएं आरम्भ करने का निर्णय लिया।

* बैठक में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप निजी तौर पर संचालित ज्वालाजी महाविद्यालय को सरकार द्वारा लेने का निर्णय लिया गया। इस महाविद्यालय में शिक्षकों तथा गैर शिक्षकों की विभिन्न श्रेणियों के 33 पदों के सृजन तथा इन्हें भरने का भी निर्णय लिया गया।

* मंत्रिमण्डल ने समस्त सरकारी महाविद्यालयों में वाणिज्य की कक्षाएं शुरू करने का भी निर्णय लिया।

* 50 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में विज्ञान की कक्षाएं तथा 53 पाठशालाओं में वाणिज्य पाठयक्रम आरम्भ करने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

* मंत्रिमण्डल ने सिरमौर जिले के रेणुका विधानसभा क्षेत्र के मैना में नया राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने को मंजूरी प्रदान की।

* बिलासपुर जिले की राजकीय महिला आईटीआई में चालक-कम-मकेनिक (एलएमवी) ट्रेड शुरू करने का स्वीकृति प्रदान की गई।

* मंत्रिमण्डल ने सोलन जिले की राजकीय आदर्श आईटीआइ नालागढ़ में टर्नर तथा फूड प्रोडक्शन सामान्य व्यवसाय शुरू करने को भी मंजूरी प्रदान की।

* बैठक में शिक्षा विभाग में प्राधिकृत चयन समिति के माध्यम से मौजूदा नीति के आधार पर जल वाहकों के रिक्त पदों को भरने की भी अनुमति प्रदान की गई।

पद सृजित व भरना

* बैठक में सिचांई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में सहायक कैमिस्टों के 42 पद तथा प्रयोगशाला सहायकों के 43 पदों को भरने को मंजूरी।

* अभियोजन निदेशालय में सहायक जिला न्यायवादी (प्रथम श्रेणी) के 18 पदों को भरने की स्वीकृति।

* डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के 15 पद भरने को मंजूरी।

* भाषा, कला तथा संस्कृति विभाग में अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के 10 पद भरने को मंजूरी।

* डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद राजकीय मेडिकल क लेज टांडा में आउटसोर्सिस के आधार पर डाटा इंटरी आप्रेटर के 14 पदों को भरने की स्वीकृति।

* बैठक में नगर परिषदों में कार्यकारी अधिकारियों के आठ पद तथा नगर पंचायतों में सचिवों के सात पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने को मंजूरी।

* चौधरी सरवण कुमार हि.प्र. कृषि विश्वविद्यालय में अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के पांच पदों को भरने को मंजूरी।

* आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र पांवटा साहिब के लिए पांच पदों के सृजन/भरने का निर्णय।

* उच्च शिक्षा निदेशालय में अनुबंध आधार पर खेल छात्रावासों के लिए खेल कोच के चार पद भरने को मंजूरी।

*** अन्य निर्णय**

* मंत्रिमंडल ने शिमला जिला के रामपुर में विभिन्न श्रेणियों के 13 पदों के सृजन के साथ नई उप जेल खोलने को स्वीकृति प्रदान की।

* बैठक में कांगड़ा जिला के भवारना में उप तहसील खोलने की स्वीकृति।

* बैठक में कोठीपुरा में एम्ज के प्रास्तावित स्थापना के दृष्टिगत बिलासपुर योजना क्षेत्र की परिधि को बढ़ाने को मंजूरी।

* बैठक में घुमारवी योजना क्षेत्र तथा भोटा योजना क्षेत्र के संशोधन को स्वीकृति।

* बैठक में सिरमौर जिला के पांवटा खण्ड की पलहोरी पंचायत को पिछड़ी पंचायती श्रेणी में रखने को स्वीकृति।

* बैठक में भारतीय खाद्य निगम को मण्डी जिला के कांगनी में गोदाम/स्टोर के निर्माण के लिए पचास वर्ष के लिए एक रुपये प्रति वर्ष पट्टे पर सरकारी भूमि देने का निर्णय।

* बैठक में कुल्लू जिला के आनी में अग्निशमन पोस्ट को वांछित स्टाफ व वाहनों सहित स्थापित करने का निर्णय।

* बैठक में मुख्यमंत्री के घोषणा के अनुरूप शिमला जिला के रोहडू तहसील के कुठाड़ा में वांछित स्टाफ सहित नया पशु अस्पताल खोलने को स्वीकृति।

* बैठक में सामाजिक सुरक्षा पैंशन का लाभ देने के लिए 'ट्रांसजेंडर' को शामिल करने को मंजूरी।

* बैठक में केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान बद्दी में पालयट आधार पर व्यवसायिक कौशल विकास पाठयक्रमों को आरम्भ करने की मंजूरी प्रदान। इस निर्णय से सामाज के गरीब व कमजोर वर्ग लाभान्वित होंगे।

* बैठक में पालमपुर लोक निर्माण उपमण्डल के तहत खैड़ा स्थित हि.प्र. लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में अतिरिक्त आवासीय सुविधा निर्मित करने को मंजूरी।

बैठक में पुलिस मैडल प्राप्त करने वाले पुलिस निरीक्षकों को दो अग्रिम वेतनवृद्धियों देने का निर्णय लिया गया। बैठक में सिरमौर जिला के कृषि विभाग के खेरी फार्म की भूमि को छठी आई आर बी बटालियन स्थापित करने के लिए गृह विभाग को हस्तांतरित करने का भी निर्णय लिया गया।

अधिनियम एवं नियम

बैठक में खनन पट्टे के लिए हिमाचल प्रदेश लघु खनिजों (छूट) एवं खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं स्टोरेज रोकथाम) नियम, 2015 में अधिसूचित दूरी के मापदण्डों में छूट प्रदान करने को मंजूरी प्रदान की।

बैठक में हिमाचल प्रदेश गौवंश सर्म्वधन बोर्ड के संविधान में संशोधन करने को स्वीकृति।

मंत्रिमंडल ने इस माह के 31 मई को सेवानिवृत्त होने वाले मुख्य सचिव पी. मित्रा की उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सराहना प्रस्ताव पारित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मित्रा अन्य अधिकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत है और उन्होने प्रदेश के विकास एवं लोगों के लिए अपनी बहुमूल्य सेवाएं प्रदान की हैं। मंत्रिमंडल ने मित्रा के लम्बे व स्वस्थ जीवन की कामना की।

बीसीसीआई अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार हमीरपुर पहुचने पर अनुराग ठाकुर का स्वागत

शिमला/शैल। अनुराग ठाकुर के बीसीसीआई के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अपने गृह जिला हमीरपुर पहुंचने पर बचत भवन में नागरिक

अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया जिसमें अनुराग ठाकुर का पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। वहीं दर्जनों संगठनों ने अनुराग ठाकुर को हार व फूल देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर भाजयुमो के राष्ट्रीय सचिव नरेन्द्र अत्री व प्रदेशाध्यक्ष सुनील ठाकुर ने भी हार पहनाकर व तलवार भेंट कर अनुराग ठाकुर को सम्मानित किया। कार्यक्रम में पूर्व शिक्षामंत्री आईडी धीमान, जिला अध्यक्ष अनिल ठाकुर, अजय शर्मा, भी मौजूद रहे।

बचत भवन में बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने अपनी ताजपोशी पर जनता व कार्यकर्ताओं का तहे दिल से आभार जताया और कहा कि जनता की बदौलत ही आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं। उन्होने कहा कि छोटे मन से कभी कोई बडा नहीं होता और राजनीति के लिए मन बडा करना पडता है। उन्होने कहा कि जो हिमाचल नंबर वन में होता है और 22 वें नंबर पर पहुंच गया है जिसके लिए प्रदेश सरकार जिम्मेदार है।

हिमाचल प्रदेश सरकार के अडियल रवैया व बार बार झूठे केसों को बनाने की बात पर मंच पर भाषण दे रहे बीसीसीआई के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर भावुक हो गए और मंच पर उनकी आंखों से आंसू झलक पडे। कुछ देर के लिए भाषण रोककर अपने आप को अनुराग ने संभाला। इसके बाद अनुराग ठाकुर ने प्रदेश कांग्रेस को जमकर कोसा और अपना गुब्बार निकाला।

बीसीसीआई के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर के हमीरपुर में हुए भव्य स्वागत में मंच पर भाषण देते समय भावुक हो गए और अपनी इस उपलब्धि के लिए जनता का तहे दिल से आभार जताया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज इस मुकाम पर पहुंचने के लिए कार्यकर्ताओ और जनता का अपार प्यार मिला है तभी बुलंदी को छुआ है। अनुराग ठाकुर ने प्रदेश सरकार को कोसते हुए कहा कि हिमाचल में कभी क्रिकेट पर राजनीति कम होगी क्योंकि हिमाचल मे क्रिकेट राजनीति की भेंट चढ चुका है। उन्होंने कहा कि आज धर्मशाला में अंतरराष्ट्रीय स्तर के मैच हुए है तो इसके पीछे कडी मेहनत की गई है।

अनुराग ठाकुर ने वीरभद्र सरकार को भारत पाक मैच रद्द करवाने की बात पर जमकर कोसा और कहा कि भारत पाक मैच रद्द होने से प्रदेश को नुकसान हुआ है। सरकार के रवैये के चलते मैच नही हो सका है। वीरभद्र सिंह ने झूठे केस मेरे उपर बनाए है। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर को इससे नुकसान नही हुआ बल्कि प्रदेश को नुकसान हुआ है।

सूचना एवं जन सम्पर्क मंत्री से शिमला प्रेस क्लब की नव निर्वाचित कार्यकारिणी की भेंट

शिमला/शैल। सूचना एवं जन सम्पर्क मंत्री मुकेश अग्निहोत्री से शिमला प्रेस क्लब की नव निर्वाचित कार्यकारिणी ने अध्यक्ष धनजय शर्मा के नेतृत्व में भेंट की।

प्रतिनिधिमण्डल ने मंत्री को प्रेस क्लब द्वारा भविष्य में किए जाने वाले कार्यों व योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने मंत्री से पत्रकार वर्ग के कल्याण संबंधी मामलों पर भी चर्चा की।

अग्निहोत्री ने प्रतिनिधिमण्डल को सरकार द्वारा हर संभव सहायता प्रदान करवाने का आश्वासन दिया तथा कहा कि प्रदेश सरकार के मीडिया के साथ हमेशा सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं।

अतिरिक्त मुख्य सचिव वी.सी. फारका भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

शिमला प्रेस क्लब के अध्यक्ष धनजय शर्मा ने मंत्री को पुष्पगुछ भी भेंट किया। उन्हो ने अग्निहोत्री से शिमला प्रेस क्लब आने का भी निमंत्रण दिया। अग्निहोत्री शिमला प्रेस क्लब के आजीवन सदस्य है।

कार्यकारिणी के सदस्य प्रतिभा कवंर, यादवेन्द्र, उज्जवल शर्मा, देवेन्द्र हेटा, रमन शर्मा, भूपेन्द्र सिंह, विकास शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार डा. शशिभूषण, संदीप उपाध्याय, हिम किरण मांटा और मुनीष शर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

उद्योगों के लिए बिजली के दाम न बढ़ाने के फैसले का सी.आई.आई.ने किया स्वागत

शिमला/शैल। भारतीय उद्योग परिसंघ ने हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा राज्य में उद्योगों को दी जा रही बिजली के दाम की दरों को न बढ़ाने बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया है। बिजली के दाम न बढ़ाने से राज्य के उद्योगों को बढने में और अधिक मदद मिलेगी और राज्य में और तेजी से उद्योगों की स्थापना होगी।

हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने हाल ही में 2016-17 के लिए बिजली के बढ़े हुए टैरिफ की घोषणा की है जिसमें डोमेस्टिक उपभोक्ताओं के लिए प्रति यूनिट 15-20 पैसे की बढ़ोत्तरी की गई है। हालांकि उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उनके लिए पूर्व के ही टैरिफ जारी रखें हैं। उद्योगों को छोड़कर अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए भी 10 से 25 पैसे प्रति यूनिट की मामूली बढ़ोत्तरी की गई है।

हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने पाया था कि राज्य के बिजली बोर्ड को 4966.05 करोड़ रुपए की जरूरत है जबकि उनकी आय वर्तमान में 4811.58 करोड़ रुपए है। बिजली के टैरिफ बढ़ाने के साथ ही राज्य सरकार ने मांग को पूरी करने के लिए अन्य प्रकार के चार्ज लागाएं हैं ताकि 154.48 करोड़ की मांग को पूरा किया जा सके। कमिशन ने इसके साथ ही डिमांड चार्ज में 20, 50 और 75 रुपए मध्यम, बड़े व ईएचटी के लिए लागू किए हैं। सी.आई.आई. की हिमाचल प्रदेश स्टेट काउंसिल के चेयरमैन संजय खुराना ने कहा कि बिजली की दरों को न बढ़ाने का राज्य सरकार का फैसला सराहनीय है। उद्योगों का इसका सीधे तौर पर फायदा मिलेगा और इससे उद्योगों को उन्नत होते देखा जा सकेगा। रिवेन्यू गैप 154.48 करोड़ रखना उद्योगों के लिए राहत भरा है। सी.आई.आई. हिमाचल प्रदेश स्टेट काउंसिल के उपाध्यक्ष राजेश साहू ने कहा कि कमिशन ने एच.पी.एस.बी.एल. को सुझाव दिया था कि वे अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करें ताकि उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं मुहैया करवा सके।

अध्यापकों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए स्थापित होगा निरीक्षण निदेशालय

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से विद्यार्थियों की, विशेषकर प्राथमिक पाठशालाओं में मासिक अथवा त्रैमासिक परीक्षा प्रणाली को आरम्भ करने के पक्षधर हैं, ताकि उनके प्रदर्शन का बेहतर आंकलन किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बच्चे के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने तथा कमजोर विद्यार्थियों के प्रति और अधिक ध्यान देने के साथ-साथ अध्यापकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने की भी आवश्यकता है।

वीरभद्र सिंह ने यह बात उच्च एवं प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के उप-निदेशकों, जिला परियोजना अधिकारियों एवं उच्च पाठशालाओं के प्रधानाचार्यों तथा कलस्टर प्रमुखों के लिए हिमाचल प्रदेश में गुणात्मक शिक्षा पर आयोजित सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अध्यापकों को परीक्षाओं से प्रत्येक बच्चे के प्रदर्शन तथा पाठशालाओं में शिक्षा के स्तर का पता चलेगा। उन्होंने कहा कि पढ़ाई में कमजोर बच्चों को प्रोत्साहित करना तथा उन्हें दक्ष बनाने के लिए व्यक्तिगत तौर पर उनका ध्यान रखना अध्यापकों का नैतिक दायित्व है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार स्कूलों में बायोमिट्रिक मशीनें लगाने पर विचार कर रही है, ताकि समय की पाबंदी को सुनिश्चित बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि अनुपस्थिति पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से पहले चरण में 136 पाठशालाओं में जुलाई माह तक बायोमिट्रिक मशीनें लगा दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस तरह की और मशीनें पाठशालाओं में चरणबद्ध तरीके से स्थापित की जाएंगी।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों को अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए बेहतर विकल्प प्रदान करने के लिए ललित कला, संगीत व विज्ञान इत्यादि विषयों के विशेष कॉलेज खोलने पर विचार कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पर्याप्त शिक्षण संस्थान खोले जा चुके हैं और अब वर्तमान स्कूलों में सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाकर तथा गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए रिक्त पदों को भर कर इन्हें सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। राज्य में निरीक्षण निदेशालय के गठन की बात को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निदेशालय में प्रशिक्षित अध्यापकों को नियुक्त किया जाएगा जो अध्यापकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करेंगे और उन्हें उचित कारवाई करने तथा स्कूलों का उचित निरीक्षण करने की शक्तियां दी जाएंगी।

उन्होंने कहा कि अध्यापकों का ध्येय विद्यार्थियों को परीक्षा उत्तीर्ण करवाना ही नही होना चाहिए बल्कि उन्हें विद्यार्थियों को मेरिट में ले जाने के लिए प्रयास करने होंगे। यदि अध्यापक अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए समर्पण भाव से कार्य करें तो उनके विद्यार्थी मेरिट हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव अध्यापकों एवं विद्यार्थियों दोनों के लिए बेहतर होगा।

अतिरिक्त मुख्य सचिव पी.सी. धीमान ने कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए अनेक पग उठाए हैं तथा विद्यार्थियों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। लड़कियों को विश्वविद्यालय स्तर तक किसी भी प्रकार का शुल्क नही है तथा जमा एक व जमा दो के विद्यार्थियों तक को भी निःशुल्क वर्दी प्रदान की जा रही है।

उच्च शिक्षा निदेशक दिनकर बुराथोकी ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि गत तीन वर्षों के दौरान जेबीटी अध्यापकों के 1197, स्नातक अध्यापकों के 1533 और सी एण्ड वी के 847 नए पद सीधी भर्ती से भरे गए। उन्होंने कहा कि स्कूलों में अध्यापकों की कमी से निपटने के लिए सभी जिलों में जेबीटी अध्यापकों की युक्तिकरण प्रक्रिया लगभग पूरी की जा चुकी है। प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक मनमोहन शर्मा ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसके पश्चात, मुख्यमंत्री ने फागली में 8 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले संस्कृत कॉलेज की आधारशिला भी रखी।

रयात बाहरा यूनिवर्सिटी ने बीटैक एमबीए कोर्सो के लिए नामी कंपनियों से करार

शिमला/शैल। एजूकेशन के अपने कारोबार को आगे बढ़ाते हुए रयात बाहरा यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने बीटैक व एमबीए कोर्सो को इंडस्ट्री की मांग के अनुरूप करने के लिए दुनिया की नामी कंपनियों गूगल, ऑरेकल, एप्पल, आईबीएम के अलावा बॉबे स्टॉक एक्सचेंज और टीडीएस के साथ करार किए है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचई के उस दावे को जिसमें पिचई ने कहा था कि गूगल को 2020 तक अकेले भारत में बीस लाख एंड्रायड डवलपर्स चाहिए, का हवाला देते हुए कहा कि रयात बहारा यूनिवर्सिटी ने इस बारे गूगल के साथ बातचीत करके बीटैक में एंड्रायड डवलपमेंट व डिजीटल मार्किटिंग में एमबीए के कोर्स डिजाइन किए है। ये कोर्स अगस्त से शुरू हो जाएंगे। बाहरा ने कहा कि बीटैक की सालाना फीस एक लाख बीस हजार के करीब होगी व एमबीए की इसे 15-20हजार रुपए ज्यादा हो सकती है।इसके अलावा दुनिया की नामी यूनिवर्सिटी ऑरेकल के साथ भी करार किया गया है जिसके तहत बीटैक व एमबीए के कोर्सों को ऑरेकल यूनिवर्सिटी ने डिजाइन किया है। आईबीएम के साथ कंप्यूटर साइंस में क्लाड कंप्यूटिंग व साइबर सिक्योरिटी एंड फोरेंसिक में बीटैक के अलावा एमबीए को लेकर करार किया गया है। एप्पल के साथ आइफोन आपरेटिंग सिस्टम में बीटैक का कोर्स शुरू किया जा रहा है। और बाबे सटक एक्सचेंज के साथ मिलकर भी फाइनेशनल मैनजमेंट में कोर्स शुरू किया जाएगा। रयात बाहरा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर राज सिंह ने नए शुरू किए जाने वाले कोर्सो की खासियत ये होगी कि इसमें प्लेसमेंट के लिए इन कंपनियों के अधिकारियों, बाहरा के टीचर व स्टूडेंट्स की एक संयुक्त समिति गठित की जाएगी।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

स्कैंडल की गप–शप

क्या रैगुलेटरी कमीशन का अध्यक्ष पद जुलाई तक खाली रहेगा

शिमला/शैल। प्रदेश के शिक्षण संस्थानों पर नियामक की भूमिका निभाने वाले रैगुलटरी कमीशन का अध्यक्ष पद अप्रैल के पहले सप्ताह से खाली चला आ रहा है सरकार ने इस पद को विज्ञापित करने में भी काफी देर लगा दी है लेकिन विज्ञापित करते समय इसमें सदस्य का एक पद और सृजित कर दिया गया। आवेदको ने अध्यक्ष और सदस्यों के रिक्त स्थानों के लिये एक साथ आवेदन किया। परन्तु सरकार ने सदस्य का पद भरने के लिये एक तीन सदस्यों की कमेटी गठित करके इस पद को भर लिया। परन्तु अध्यक्ष का पद भरने के लिये कमेटी का गठन नही किया जा सका है।

कमीशन के नियमों के मुताबिक शिक्षा सचिव ही यह पद भरने के लिये पदेन सदस्य सचिव है। इस समय अतिरिक्त मुख्य पी सी धीमान के पास शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी है लेकिन पी सी धीमान भी इस कमीशन के अध्यक्ष पद के लिये स्वयं एक आवेदक है। ऐसे में जब तक पी सी धीमान के पास सचिव शिक्षा की जिम्मेदारी है तब तक वह स्वयं आवदेक होने के नाते इस पद को भरने की प्रक्रिया शुरू नही कर सकते। अब यह सवाल उठता जा रहा है कि जब कमीशन का अध्यक्ष पद ही खाली चल रहा है तब वहां बैठे सदस्य क्या काम कर पा रहे होंगे और उनके काम का औचित्य क्या रह जायेगा। पी सी धीमान जुलाई में सेवा निवृत हो रहें है। इस लिये यदि सरकार इस पद को भरने की गंभीरता के प्रति ईमानदार तो उसे पी सी धीमान से शिक्षा की जिम्मेदारी लेकर किसी और को देनी होगी ताकि नया आदमी अध्यक्ष पद को भरने की प्रक्रिया को तो शुरू कर पाये। इस अध्यक्ष पद के आवेदकों में पी सी धीमान के साथ ही एक प्रमुख नाम आई पी एस अधिकारी वी एन एस नेगी का भी है। नेगी की सेवा निवृत्ति इसी वर्ष नवम्बर में है। नेगी भी मुख्य मन्त्री के विश्वास पात्रों में गिने जाते है ओर पी सी धीमान भी उसी विश्वस्तता की पंक्ति में खडे है लेकिन पीसी धीमान के खिलाफ एच पी सी ए के एक मामले में अभियोजन की स्वीकृति सरकार ने दे रखी है। इस परिदृष्य में अब यह सरकार के लिये एक परीक्षा की घडी मानी जा रही है कि वह धीमान और नेगी में से किसे चुनती है।

इस तरह सरकार के लिये मुख्य सूचना आयुक्त का पद भरना भी एक समस्या माना जा रहा हैं। क्योकि इस पद के विज्ञापित होने से पहले ही चार लोग इसके लिये आवदेन भेज चुके है जिनमें केन्द्र सरकार में उच्च शिक्षा सचिव रहें अशोक ठाकुर और सेवा निवृत हो रहे मुख्यसचिव पी मित्रा प्रमुख है। अब यह पद विज्ञापित हो चुका है और इसके आवेदन की अन्तिम तारीख 23 जून है ऐसे मे 23 जून तक कितने और आवेदक आ जाते है तथा पुरांने आवेदकों को नये सिरे से आवदेन की आवश्यकता पड़ती है या नही अभी यह स्पष्ट होना बाकि है। अशोक ठाकुर और पी मित्रा दोनों मुख्य मंत्री के विश्वस्त माने जाते है। लेकिन इसी बीच यह भी चर्चा सामने आ गयी है कि प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के एस तोमर भी मुख्य सूचना आयुक्त के प्रबल दावेदारों में है। के एस तोमर को मुख्य मन्त्री का बहुत ही विश्वसनीय माना जाता है। लेकिन तोमर के लिये संविधान में रोक है। संविधान के मुताबिक केन्द्र या राज्य सरकारों के लोक सेवा आयोगों के सदस्य/अध्यक्ष राज्य सरकार या केन्द्र सरकार में कोई पद स्वीकार नही कर सकते हैं। यह लोग किसी भी लोक सेवा आयोग में तो स्थान पा सकते हैं लेकिन सरकार में नही। लेकिन उच्चस्थ सूत्रों के मुताबिक मुख्यमन्त्री तोमर को ही सी आई सी बनाना चाहते है और इसके लिये वह संविधान की भी अनदेखी करने को तैयार है माना जा रहा है कि तोमर की संभावित उम्मीदवारी के कारण ही इस पद के आवेदनों के लिये 23 जून की तारीख पी मित्रा की सेवा निवृति के बाद की रखी गयी है इस समय मुख्य सविच रैगुलैटरी कमीशन का अध्यक्ष पद और मुख्य सूचना आयुक्त के पद भरना मुख्य मन्त्री के लिये काफी समस्या बन गये है।

रेणु साहनी धर और सी पी सुजाया की कड़ी में उपमा चौधरी

प्रदेश का मुख्यसचिव कौन होता है इस पर प्रदेश की निगाहें लगी हुई हैं। मुख्यमन्त्री किस पर अपना भरोसा जताते हैं और उस भरोसे का आधार क्या रहेगा इसका खुलासा तो आने वाले दिनों में आमने आयेगा। लेकिन यह तय माना जा रहा है कि वीरभद्र शासन में किसी महिला का मुख्यसचिव बन पाना संभव नही है। इस समय वरियता में दीपक सानन और विनीत चौधरी के बाद उपमा चौधरी का नाम आता है। उपमा का दामन एक–दम पाक साफ है। उसकी एसीआर भी outstanding है। लेकिन इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री उस पर भरोसा जताने को तैयार नहीं है। माना जा रहा है कि वीरभद्र की नजरें इनायत उनके करीबी वी सी फारखा पर रहेगी।

लेकिन इस मौके पर सचिवालय के गलियारों से लेकर सकैण्डल तक एक चर्चा अवश्य आ गई है। और इस चर्चा में पूर्व में मुख्यसचिव पद के लिए नजरअन्दाज हुई दो महिला अफसरों का नाम सबकी जुबान पर आ गया है। पूर्व में वरिष्ठ आई ए एस अधिकारी रेणु साहनी धर और सी पी सुजाया के नाम लोग याद कर रहे हैं। इन अधिकारियों को भी मुख्य सचिव की ताजपोशी से वंचित रखा गया था। आज यदि वी सी फारखा मुख्य सचिव का पद पाने में सफल हो जाते हैं तो कांग्रेस और वीरभद्र के साथ यह जुड़ जाएगा कि वह महिला अधिकारियों को मुख्य सचिव जैसे पद के योग्य ही नहीं मानते हैं क्योंकि उपमा चौधरी का नाम इस कड़ी में तीसरा जुड़ जायेगा।

इस समय आई ए एस और आई पी एस तथा अन्य सेवाओं में दर्जनों महिला अधिकारी है। इन अधिकारियों के मनोबल पर किस तरह का असर पड़ेगा और यह अधिकारी कांग्रेस और वीरभद्र सिंह को लेकर इस संदर्भ में किस तरह की धारणा बनाते हैं इसका खुलासा भी आने वाले दिनों में ही सामने आयेगा। लेकिन इन दिनों बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ आदि के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उन कार्यक्रमों पर भी यह सवाल तो अवश्य ही उठेगा कि क्या हम ईमानदारी से ही इन कार्यक्रमों को अंजाम दे रहे हैं या फिर केवल एक रस्म अदायगी ही निभाई जा रही है। उधर कुछ सिरफिरे इस नजरअन्दाजी को आने वाले चुनावों में कांग्रेस और वीरभद्र के महिला आदर सम्मान की सच्चाई के रूप में भी भुनाने का प्रयास करने की योजना अभी से ही बनाने लगे हैं।

ठेकेदारों पर मेहरबान

.....पृष्ठ 1 का शेष

सीमा के भीतर काम नही कर पाये तो क्या उन पर इस देरी के लिये कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा इसको लेकर भी विभाग स्पष्ट नहीं है। विभाग द्वारा करवाए जा रहें कामों के रेट को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं चल रही है क्योंकि जब 17.50 करोड़ में चर्च की रिपेयर करवाये जाने का अनुबन्ध सामने आया था तभी से पर्यटन विभाग द्वारा करवाये जा रहे काम चर्चा का विषय बने हैं।

मुख्य सचिव लेता रहा भारी रिश्वत बोले भंडारी, आलूवालिया पर भी बोला हमला

शिमला/शैल। विवादास्पद फोन टेपिंग कांड में सीजेएम की अदालत से बरी होने के बाद पूर्व डीजीपी आई.डी.भंडारी ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से उन्हें इस तरह प्रताड़ित व अपमानित करने को लेकर जवाब तलब किया है। भंडारी ने मुख्य सचिव पी मित्रा को भ्रष्टाचारी करार देते हुए कहा कि प्रदेश का ये आईएएस अफसर हजारों में नही लाखों में रिश्वत लेता रहा है। ये भारी रिश्वत लेता रहा है। जब इसे चीफ सेक्रेटरी बनाया जा रहा था तो इसके खिलाफ विजीलेंस केस चल रहे थे। आनन फानन में उन्हें क्लीन चिट दी गई और चीफ सेक्रेटरी बनाया गया।

भंडारी ने कौल सिंह के बाद आज वीरभद्र सिंह के लाडले आईपीएस अफसर एपी सिंह पर सीधा सीधा हमला बोला और कहा कि एपी सिंह, एक इंस्पेक्टर, मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव रहे सुभाष आहलुवालिया ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के कान भरे व उन्हें उनके खिलाफ भड़का दिया। इन सबने मिलकर वीरभद्र सिंह को बताया कि चंडीगढ़ में उनकी बगिंग की गई। अब सीजेएम की अदालत ने कहा कि कोई मामला ही नही बनता तो ऐसे में वीरभद्र सिंह को प्रदेश की

जनता को जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जितना उन्होंने झेला उससे कम से कम इस सबके लिए जिम्मेदार लोग आधा भी झेले इसका को प्रयास करेंगे। इस बावत वो अपने वकीलों से विचार कर रहे है। उन्होंने दोहराया कि उनका लोकतंत्र व कानून पर भरोसा है।

भंडारी ने कहा कि वीरभद्र सिंह की सरकार में ईमानदार अफसर घुटन महसूस कर रहे है। जो ईमानदार, निर्दोष है वे पीड़ित है।

याद रहे है पी मित्रा चीफ सेक्रेटरी की कुर्सी से इसी महीने के आखिर में रिटायर हो रहे है। भंडारी ने मित्रा को चुनौती दी कि वो उनके खिलाफ मानहानि का दावा दायर करें। वो सारा सच अदालत में पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसा चीफ सेक्रेटरी बना है ये अपने आप शर्मनाक है। उधर, आहलुवालिया पर ईडी ने शिकंजा कसा हुआ है तो एपी सिंह आजाद है।

उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह सरकार ने उन्हें अवैध तरीके से हटाया था। रात को डीपीसी की गई व फोन टेपिंग का मुद्दा उछाला गया। ये झूठा केस था। हैरानी की बात यह है कि फोन टेपिंग मामले को लेकर सरकार द्वारा अदालत में दायर किए गए चालान में 14 सौ नही, बल्कि दो फोन अवैध तौर पर टेप होने की बात कही गई है। भंडारी का दावा है कि ये दोनों फोन भी अवैध तरीके से टेप नही हुए, अगर हुए हैं तो इस मामले से उनका लेना देना नही, क्योंकि फोन टेपिंग का जिम्मा डीजीपी के नही आईजी के अधीन होता है।

जो फोन टेप हुए उनमें से एक फोन किसी तिब्बती नागरिक तथा दूसरा सब्जी मंडी का है। उन्होंने कहा कि समूचे प्रकरण से उन्हें पीड़ा पहुंची है। उन्होंने कहा कि कुछेक अफसरों ने अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने की खातिर मुख्यमंत्री को गुमराह किया है। अन्यथा उनके साथ मैनें बहुत साल काम किया, कभी भी मुझे तंग नही किया गया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वह अब फोन टेपिंग मामले में कानूनविदों की राय लेने के बाद इस मामले में आगामी कार्रवाई करेंगे।